वचन और कार्यः प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था) संबंधित है।

द हिन्दू

16 अगस्त, 2019

"स्वतंत्रता दिवस पर श्री मोदी द्वारा प्रस्तुत किये गये विजन को जमीनी स्तर पर कार्रवाई करते हुए पूरा करने की आवश्यकता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कुछ नए विचारों के साथ वाक्पटुता को भी दर्शाया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, जल संरक्षण और प्लास्टिक उपयोग विनियमन की आवश्यकता के बारे में बात की, जो उस महत्व को इंगित करता है जो इन विषयों के साथ संलग्न है। भारत में भयंकर जल संकट से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने सहित कुछ नीतिगत उपाय पहले से ही लागू हैं।

प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अनुपस्थिति के साथ-साथ अंधाधुंध प्लास्टिक के उपयोग ने पारिस्थितिकी को पहले से ही इस तरह बर्बाद कर दिया है कि युद्ध-स्तर पर मितव्ययी उपायों की आवश्यकता बढ़ गयी है। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की, जो सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को बेहतर बना सकती है और सैन्य-नागरिक संबंधों को इस तरह से पुनर्गठित कर सकती है जिससे वर्तमान समय की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं।

इन सभी में लोगों की भागीदारी एवं साथ ही पर्यटन और स्थानीय उद्यमों के विकास के लिए उनका आह्वान भी सही दिशा और भावना में प्रतीत हो रहा था। स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने और उपभोग करने की अपील भले ही विकास के वैश्विक नुस्खों के अनुरूप न दिखे, लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे यह कितना भी अव्यावहारिक लगे।

2014 और 2019 के बीच उनका पहला कार्यकाल लोगों की जरूरतों पर केंद्रित था, जबकि दूसरा जो इस साल शुरू हुआ है उन्होंने वादा किया है, कि वह सभी आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जो 70 दिनों में हासिल किया है, वो पिछली सरकारें 70 वर्षों में भी नहीं कर सकी थीं।

उन्होंने एक आशावादी सोच को प्रकट करते हुए कहा कि गरीबी को समाप्त किया जा सकता है और इसे हर हाल में समाप्त किया भी जाएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 73वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद, भारत को आशावादी रहने की आवश्यकता है।

हालांकि, श्री मोदी ने अपने भाषण में अर्थव्यवस्था में छाये संकट के बादलों और देश के सामाजिक ताने-बाने में व्याप्त खतरों पर पर्दा डालने की कोशिश की। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अतीत में जिस प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया है, उसे देखते हुए, यह अगले पांच वर्षों में 5-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने के रास्ते पर हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बार ग्रामीण एवं शहरी मांग और निवेश में मौजूद मंदी को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करने का विकल्प चुना।

हालांकि, उन्होंने उन उद्यमियों को आश्वस्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयास जरूर किया, जो हाल ही में कर सक्रियता के कारण आशंकित थे। श्री मोदी ने इन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा कि धन सृजन करने वालों को किसी भी हाल में तंग नहीं

किया जायेगा और व्यवसायियों को निवेश करने का आह्वान किया। लेकिन जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर को अपनी विशेष संवैधानिक स्थिति से अलग करने के अपने फैसले पर बात शुरू की, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जम्मू-कश्मीर को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए थोड़ा वक्त और लग जायेगा। एकांगी योजनाओं के विस्तृत उल्लेख में उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक कर' (जो पहले से ही लागू है) और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना का उल्लेख किया।

इस तरह की व्यापक योजनाएं उनकी दृष्टि के अनुकूल हैं और इनका भाषण इसी सोच को दर्शाता भी है। लेकिन अगर भारत को बेहतर स्थिति में आने के लिए एक नए पाठ्यक्रम को अपनाना ही है, तो उसे लाल किले से दिए गये भाषण की भव्यता से पार जाना होगा। श्री मोदी को अपने भाषण का ठीक उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिए, जिस प्रकार सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह एक-दूसरे का अनुसरण करते हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)

लेखक - निरुपमा सुब्रमण्यन (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (आंतरिक सुरक्षा) संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

16 अगस्त, 2019

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिक्र किया गया, यह क्या है? यह विचार कहाँ से आया और सीडीएस का कार्य कहाँ तक विस्तृत है? इस आलेख में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, सशस्त्र बलों के तीनों विंगों को 'शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व' प्रदान करने और उनके बीच समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा की है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का कार्यालय किससे संबंधित है?

सीडीएस एक उच्च सैन्य कार्यालय है, जो तीनों सैन्य सेवाओं के कामकाज की देखरेख और उसका समन्वय करेगा, दीर्घकालिक रक्षा योजना पर कार्यकारी (भारत के मामले में, प्रधानमंत्री को) के लिए सहज त्रि-सेवा विचार और श्रमशक्ति, उपकरण और रणनीति, तथा सबसे बढ़कर, संचालन में जॉइंटमैनशिप सहित लंबी अवधि की रक्षा योजना और प्रबंधन पर कार्यकारी (भारत के मामले में, प्रधानमंत्री को) के लिए सहज-त्रिकोणीय सेवा विचार और एकल-बिंदु सलाह प्रदान करेगा।

अधिकांश लोकतंत्रों में, सीडीएस को अंतर-सेवा प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत सैन्य प्रमुखों के तत्काल परिचालन पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता है। संघर्ष के समय में सीडीएस की भूमिका और महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

उन्नत सैन्य शक्ति वाले अधिकांश देशों में इस तरह के पद उपलब्ध होते हैं, जिनमें सत्ता और अधिकार की अलग-अलग डिग्री होती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के चेयरमैन संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC)] एक शक्तिशाली जनादेश और विस्तृत शक्तियों के साथ बेहद शक्तिशाली है।

ये राष्ट्रपति के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सैन्य सलाहकार होते हैं और उनका नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, होमलैंड सिक्योरिटी काउंसिल और रक्षा सचिव तक फैला हुआ है।

यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, मरीन कॉर्प्स और नेशनल गार्ड के प्रमुख भी जेसीएससी के सदस्य हैं। CJCSC सहित सभी, फोर स्टार अधिकारी हैं, लेकिन कानून द्वारा केवल CJCSC को 'प्रमुख सैन्य सलाहकार' के रूप में नामित किया गया है।

तो, भारत ने अब तक सीडीएस क्यों नहीं नियुक्त किया था?

भारत में इसके समकक्ष एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) के अध्यक्ष होते हैं; लेकिन जिस तरह की इसकी बनावट है, उसके आधार पर यह शक्तिहीन प्रतीत होता है। तीन सैन्य प्रमुखों के बीच वरिष्ठतम अधिकारी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो एक ऐसा कार्यालय होता है, जो पदस्थ की सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है।

वर्तमान में CoSC के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ हैं, जो 31 मई को नौसेना स्टाफ के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के बाद आये थे। एसीएम धनोआ सितंबर, 2019 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे, तब उन्होंने केवल चार महीने का कार्यकाल पूरा किया होगा।

2015 में, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने CoSC व्यवस्था को 'असंतोषजनक' और इसके अध्यक्ष को 'नाममात्र शासक' के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा था कि इस पद में त्रि-सेवा का एकीकरण नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप

अक्षमता और संपत्ति का दोहराव हुआ था।

CoSC प्रणाली की उपेक्षा औपनिवेशिक युग से की जाती रही है, जिसमें केवल कुछ वर्षों में मामूली बदलाव किए गए हैं। एक शक्तिशाली सैन्य नेता के बारे में राजनीतिक वर्ग में आशंकाओं के साथ-साथ अंतर-सेवा विवाद (inter-Services bickering) ने लंबे समय तक पद के उन्नयन को विघटित करने का काम किया है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए पहला प्रस्ताव 2000 कारगिल रिव्यू कमेटी (केआरसी) से आया था, जिसने रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल मुख्यालय के बीच 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन और सर्वोच्च निर्णय लेने तथा संरचना एवं इंटरफेस के संपूर्ण पहुँच' के पुनर्गठन के लिए सिफारिश की थी। कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट और सिफारिशों का अध्ययन करने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को प्रस्ताव दिया कि एक सीडीएस, जो फाइव स्टार अधिकारी होगा, बनाया जाए।

पोस्ट की तैयारी में, सरकार ने 2002 के अंत में एकीकृत रक्षा स्टाफ (आईडीएस) बनाया, जिसे सीडीएस सचिवालय के रूप में कार्य करना था। हालांकि, पिछले 17 वर्षों में, यह सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर अभी तक एक और अस्पष्ट विभाग बना हुआ है।

लेकिन इस प्रस्ताव का क्या हुआ?

विशेष रूप से इस तरह के कदम का विरोध करने के साथ, सेवाओं के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई। तब कांग्रेस, सीडीएस के पद पर बहुत अधिक सैन्य शक्ति केंद्रित करने के विचार के खिलाफ थी। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भी, समान कारणों से इसका सूक्ष्म रूप से विरोध किया था।

'रक्षा मंत्रालय, जो आखिरी चीज चाहता था वह सीडीएस की प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक सीधी पहुंच थी।' जनरल पनाग के अनुसार, सीडीएस के विचार को लागू नहीं किया जा सकने का एक बड़ा कारण यह था कि रक्षा मंत्रालय के नौकरशाह तीनों सेवाओं पर अपनी शक्ति का त्याग करने के लिए ढीले थे। नतीजतन, रक्षा मंत्रालय ने एक सेवा के खिलाफ दूसरे का इस्तेमाल किया। 'इसके अलावा,' जनरल पनाग ने कहा, 'प्रत्येक सेवा का अपना लोकाचार होता है और प्रमुखों को लगता है कि सीडीएस के तहत, उन्हें आभासी गैर-मौजूदगी प्रदान की जाएगी।'

छोटे वायु सेना और नौसेना को डर है कि सीडीएस सेना से सबसे बड़ी सेवा होगी। भारतीय वायुसेना ने लंबे समय से तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी सैन्य दलों के विपरीत, भारतीय सैन्य सेवा एक अभियान बल नहीं है, जिसके लिए एक सीडीएस की आवश्यकता पड़े।

कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट के एक दशक बाद 2011 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, जिसने विपक्ष में रहते हुए सीडीएस प्रस्ताव का विरोध किया था, ने रक्षा और सुरक्षा पर नरेश चंद्र समिति की स्थापना की। 14-सदस्यीय समिति, जिसमें सेवानिवृत्त सेवा प्रमुख और अन्य रक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं, ने सीडीएस प्रस्ताव को कम शक्ति प्रदान करने पर जोर दिया, जिसमें CoSC अध्यक्ष के पद पर फोर स्टार अधिकारी का कार्यकाल दो वर्ष के लिए निश्चित होगा। CoSC अध्यक्ष के पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तुलना में काफी अधिक अधिकार और शक्तियाँ होंगी।

सीडीएस होने का मामला क्या है?

हालांकि केआरसी ने सीधे तौर पर एक सीडीएस की सिफारिश नहीं की थी - जो कि जीओएम से आया था - इसने तीन सेवाओं के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो कारगिल संघर्ष के शुरुआती हफ्तों में खराब थी।

कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि भारत एकमात्र प्रमुख लोकतंत्र है जहाँ सशस्त्र बल मुख्यालय शीर्ष सरकारी ढांचे के बाहर है। यह देखा गया कि सेवा प्रमुख 'अक्सर नकारात्मक परिणामों के परिणामस्वरूप' अपना अधिकांश समय अपनी परिचालन भूमिकाओं के लिए समर्पित करते हैं। लंबे समय तक रक्षा की योजनाएं दिन-प्रतिदिन प्राथमिकता पर हावी हो जाती हैं। इसके अलावा, उच्च स्तर के रक्षा प्रबंधन निर्णय अधिक सहमति और व्यापकता के साथ सुनिश्चित हों, इसके लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सैन्य कमांडरों के विचारों और विशेषज्ञता का लाभ नहीं है।

GS World
Committed to Excellence

इसके विपक्ष में तर्क?

सैद्धांतिक रूप से, सीडीएस की नियुक्ति लंबे समय से जारी है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय के पास कोई स्पष्ट खाका नहीं है। भारत की राजनीतिक स्थापना को बड़े पैमाने पर अनभिज्ञ होने या सुरक्षा मामलों के प्रति सबसे अच्छा उदासीनता के रूप में देखा जाता है और इसलिए यह सीडीएस के कार्य को सुनिश्चित करने में असमर्थ है।

स्वभाव से सेना परिवर्तन का विरोध करती रही है। अमेरिका में, 1986 के गोल्डवाटर-निकोल्स एक्ट ने अध्यक्ष को 'प्रधान सैन्य सलाहकार' के बराबर में राष्ट्रपति और रक्षा सचिव के पद से ऊंचा किया। भारतीय संदर्भ में, आलोचकों को डर है, दूरदर्शिता और समझ की अनुपस्थिति सीडीएस को 'रोजगार का' एक और मामला बना सकती है।

वर्तमान में सैन्य मामलों में भारत के प्रधानमंत्री को सलाह कौन देता है?

वास्तव में यह कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA, एनएसए) का है। यह विशेष रूप से 2018 में रक्षा योजना समिति के गठन के बाद किया गया, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल इसके अध्यक्ष के रूप में थे, और विदेश, रक्षा और व्यय सचिव, एवं तीन सेना प्रमुख सदस्य के रूप में थे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **हाल ही में चर्चा में रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए-**

(a) चीफ ऑफ डिफेंस एक उच्च सैन्य कार्यालय है जो तीनों सैन्य सेवाओं के कामकाज की देख-रेख और उसका समन्वय करेगा।

(b) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राष्ट्रपति के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सैन्य सलाहकार होते हैं।

(c) वर्तमान में CoSC के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा हैं।

(d) चीफ ऑफ डिफेंस के लिए पहला प्रस्ताव 2002 कारगिल रिव्यू कमेटी से आया था।

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Identify the incorrect statement regarding the Chief of Defence Staff recently in dissussion-**

(a) Chief of Defence Staff is a high defence office which will oversee the functioning of all three military services and their cooperation.

(b) Chief of Defence Staff is the Senior most military officer and advisor to the President.

(c) At present the chairman of CoSC is Air Chief Marshal Birendra Dhanoa.

(d) The first recommendation for the Chief of Defence Staff was given by 2002 Kargil Review Committe.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुये भारत में चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालिए। **(250 शब्द)**

Q. Considering the increasing security challenges, throw light on the importance of appointment of Chief of Defence Staff. **(250 Words)**

नोट : 14 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।